बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :– 191905   पटना, दिनांक :– 12-07-14
ग्रा0वि0 5/सा0आ0ज0ग0(प्रारूप प्रका0)-103-109/2013

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार सिंह,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
–सह–
मुख्य SECC पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :– **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) अन्तर्गत COTS के तहत निष्पादित दावे/आपत्तियों का F-file NIC पर अपलोड करने के संबंध में ।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में सभी जिलों में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के अंतिम चरण का कार्य प्रगति पर है । उक्त क्रम में COTS (Claims and Objections Tracking System) के तहत प्राप्त दावे/आपत्तियों के निष्पादनोपरांत उसका अपलोडिंग NIC सर्वर पर किया जाना है ।

आप अवगत है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के पात्र लाभार्थियों का चयन SECC के प्रारूप सूची के आधार पर किया गया है । COTS के तहत राज्य में प्राप्त दावे/आपत्तियों में लगभग 29 (उन्तीस) लाख दावे/आपत्ति का अपलोडिंग NIC सर्वर पर किया जा चुका है ।

राज्य सरकार के अनुरोध के आलोक में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा COTS के तहत निष्पादित दावे/आपत्तियों के Provisional F-file के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र लाभार्थियों की सूची राज्य को उपलब्ध कराने हेतु NIC दिल्ली को निदेशित किया गया है (प्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत निष्पादित एवं NIC सर्वर पर अपलोड किये गये दावे/आपत्ति का F-file दो दिनों के अंदर NIC सर्वर पर अपलोड कराने की कृपा की जाये, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र परिवारों की सूची प्राप्त कर उसे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराया जा सके । निष्पादन हेतु लंबित आवेदनों का निष्पादन पूर्व की भांति चलता रहेगा ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन
12.7.14
(मिथिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 191905   दिनांक : 12-07-14
प्रतिलिपि – सभी उप विकास आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.7.14
(मिथिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव